# बुनियादी ढांचे से संबंधित परियोजनाओं के लिए सरकार सार्वजनिक -निजी भागीदारी को गति देने के पक्ष में

## परियोजनाओं का ठेका देने और इसके क्रियान्वयन के लिए संचालन समूह का गठन

कमजोर पड़ती अर्थव्यवस्था में मजबूती लाने के लिए मनमोहन सिंह सरकार ने अगले छह महीनों में बुनियादी ढांचे से संबंधित रेल, विद्युत, पत्तन और विमानन क्षेत्र की 1.14 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं में तेजी लाने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के तहत अगले छह महीनों में जिन प्रस्तावों को ठोस शक्ल प्रदान की जाएगी उसमें मुंबई एलिवेटेड रेल गलियारा (30,000 करोड़ रुपए), भुवनेश्वर और इम्फाल में दो अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे (20,000 करोड़ रुपए) और विद्युत तथा ट्रांसमिशन परियोजनाएं (40,000 करोड़ रुपए) शामिल है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का मानना है कि निवेश के माहौल में तेजी लाने के लिए बुनियादी ढांचे में निवेश को दुरुस्त करना होगा।

प्रधानमंत्री कार्यालय की एक विज्ञप्ति के अनुसार "वरीयता के आधार पर परियोजनाओं का ठेका देने और इसके क्रियान्वयन की निगरानी के लिए एक संचालन समूह का गठन किया गया है।" प्रधानमंत्री डॉ. सिंह की अध्यक्षता और वित्त मंत्री श्री पी. चिंदबरम तथा योजना आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. मोंटेक सिंह अहलूवालिया की उपस्थिति में आयोजित बैठक में यह निर्णय भी लिया गया कि रेल मंत्रालय रेल टैरिफ प्राधिकरण के निर्माण का प्रस्ताव जल्द ही मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत करेगा। विद्युत, कोयला, रेलवे, सड़क, नौवहन और नागर विमानन मंत्रियों ने भी इस बैठक में भाग लिया।

भुवनेश्वर और इम्फाल में दो नए अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डों का ठेका दिया जाएगा इसके अलावा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा कम लागत के 50 नए हवाईअड्डों की शुरूआत की जाएगी। इसी प्रकार पीपीपी मोड में इस वर्ष आठ ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों का ठेका दिया जाएगा ये इस प्रकार हैं- नवी मुंबई, जुहू (मुंबई), गोवा, कन्नूर, पुणे (राजगुरू नगर चकन), श्रीपेरंबदूर (तमिलनाडु), बेल्लारी और रायगढ़। पीपीपी अनुबंध के आधार पर चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, गुवाहटी, जयपुर और अहमदाबाद में हवाईअड्डे के संचालन और रखरखाव की शुरूआत की जाएगी।

कम लागत के संभावित हवाईअड्डों में आंध्रप्रदेश में विजयवाडा, नेल्लोर, कुरनूल, कडप्पा, निजामाबाद, तिरूपति, अनंतपुर, और करीमनगर, झारखंड में धनबाद, बोकारो और हजारीबाग, बिहार में मुजफ्फरपुर, छपरा और सासाराम, पंजाब में लुधियाना, जालंधर और

फिरोजपुर, उत्तरप्रदेश में आगरा, इलाहाबाद, मुरादाबाद, सहारनपुर, मेरठ, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, बिजनौर और आजमगढ़, अरूणाचल प्रदेश में तेजू, मोमदिला और अलॉन्ग, असम में सिल्चर, जोरहाट और तेजपुर, मध्य प्रदेश में ग्वालियर, सिंगरौली, बुरहानपुर, खंडवा, जबलपुर, सिद्धी और शहदौल, ओडिशा में बरहामपुर, राउरकेरा और केंदुझार राजस्थान में अजमेर, कोटा, भीलवाड़ा और अलवर तथा महाराष्ट्र में कोल्हापुर, नासिक, जलगांव, सोलापुर और अमरावती शामिल है।

प्रधानमंत्री कार्यालय की विज्ञप्ति में कहा गया कि "सार्वजनिक-निजी साझेदारी की परियोजनाओं को प्रदान की गई अनेक छूटों के मद्देनजर सड़क परियोजनाओं के ठेके देने में तेजी आनी चाहिए", "अनेक समस्याओं के कारण इस क्षेत्र की रफ्तार में जो गिरावट आई है उसकी वजह से सरकार द्वारा 2012-13 के लिए निर्धारित राजमार्ग लक्ष्य का केवल 10 प्रतिशत ही पूरा किया जा सका" वक्तव्य में यह भी कहा गया कि "अब एक्सप्रेसवे पर अधिक ध्यान केन्द्रित किया जाएगा।"

ऊर्जा के क्षेत्र में वक्तव्य में कहा गया कि सबके लिए सुगम मार्ग के संचालन के लिए अलग प्रावधान पर विद्युत मंत्रालय काम कर रहा है जबकि कोयले के उत्पादन में तेजी लाने के लिए नई नीतियां तय की जाएंगी।

रेलवे के मामले में एक अंतर-मंत्रालयी समूह का गठन किया जाएगा जिसमें रेलवे मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और योजना आयोग शामिल होगा जिसका कार्य वरीयता के आधार पर और समयबद्ध तरीके से 2,00,000 करोड़ से भी अधिक की मंजूर की जा चुकी बैकलॉग परियोजनाओं की बड़ी संख्या को दो महीने के भीतर क्लियरेंस के लिए वित्तियन तथा कार्यान्वयन प्रणाली लागू करने का होगा। विज्ञप्ति में कहा गया कि अगले छह महीने के भीतर रेल इंजन विनिर्माण की दो परियोजनाओं, एलिवेटेड रेल गलियारा, समर्पित मालभाडा गलियारा और स्टेशन के पुनर्विकास जैसी रेलवे की प्रमुख परियोजनाओं के लिए ठेका देने के लिए ध्यान केन्द्रित किया जाएगा।

(मुख्य संपादक अनुराग मिश्रा, एजेंसी और
समाचारपत्रों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर)